अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए रखी वस्तुओं की जांच के लिए भारत के प्रमुख शहरों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां गठित की गई हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के तहत वस्तुओं में से कोई एक पुरावशेष है।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन

127. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की 1979 में प्रो० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और इसने अप्रैल, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समवर्ती मूल्यांकन 1978–85 के दौरान 7 सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों द्वारा भी आयोजित किया गया और 56 मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। शीघ्र ही 14 सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान संस्थानें और अन्य एजेंसियां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का सघन मूल्यांकन पूरा करने में लगी हुई हैं। उनमें से दो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की आवृत्ति और उसकी कोटि सुधारने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। इनमें ये शामिल हैं :–

- शिक्षुओं के साथ-साथ अध्यापकों की प्रेरणा में वृद्धि।
- अध्ययन की गति, विषयवस्तु और कोटि में सुधार करना।
- सामाग्रियों के एक नये पैकेज का डिजाइन बनाना जो प्रारम्भ से ही स्व-निर्देशित, अध्ययन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगी।
- समय पर मानक अध्यापन अध्ययन सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- अध्यापन अध्ययन वातावरण और कारगर व्यवस्था सूचना पद्धति में सुधार के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान की उपलब्धियों को काम में लाना।
- कार्यक्रम के गठन और क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- साक्षरता के लिए जन आन्दोलन प्रारम्भ करना जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, अध्यापकों छात्र, युवकों, भूतपूर्व सैनिकों कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, बैंकों, सहयोगियो इत्यादि को शामिल करना है।
- उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा शुरू करना।

मध्य प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय

128. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू और आगामी शिक्षा सत्र में मध्य प्रदेश में नये केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय प्रारंभ किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में क्या मौलिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) चालू सत्र, 1989-90 के

दौरान मध्य प्रदेश में अब तक निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए जा चुके हैं :—

1. जगदलपुर, जिला बस्तर।
2. इटारसी, जिला होशंगाबाद।
3. कोरबा, जिला बिलासपुर ।
4. नौरोजाबाद, जिला शाहडोल।

अगले शैक्षिक सत्र के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । केन्द्रीय विद्यालयों पर होने वाला व्यय योजनेत्तर बजट में से वहन किया जाता है । अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

चालू शैक्षिक सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में कोई नवोदय खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है । अगले शैक्षिक सत्र अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में कोई भौतिक अथवा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

वन उत्पादों से प्राप्त आय में आदिवासियों की भागीदारी

129. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासियों के वन सम्पदा पर अधिकार के सिद्धान्त को मान कर उन्हें वन उत्पादों से होने वाली आय में भागीदारी दिलाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) वन सम्पदा पर आदिवासियों के अधिकार के सिद्धान्त को मानकर उन्हें वन सम्पदा से होने वाली आय में भागीदारी दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निर्धारित किया गया है कि वनों से अधिकार और रियायतें मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से आदिवासियों के वास्तविक उपयोग के लिए होने चाहिए । नीति में यह भी बताया गया है कि आदिवासी लोगों और वनों के बीच सहजीवी संबंध को ध्यान में रखते हुए वनों की सुरक्षा, पुनर्जनन और विकास में उन्हें घनिष्ठ रूप से शामिल किया जाए । इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि ठेकेदारों के स्थान पर यथाशीघ्र आदिवासी सहकारिता; श्रमिक सहकारितायें; सरकारी निगम आदि जैसी संस्थाएं होनी चाहिए।

GNP and Per Capita Income

130. **SHRI S. S. AHLUWALIA:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the GNP and Per Capita Income were the lowest during 1977 to 1980 and have risen thereafter; and

(b) if not, what have been the GNP and Per Capita Income, year-wise, since 1978 upto 1989, alongwith the projections for the next year?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWA NATH PRATAP SINGH): (a) During the period 1975-76 to 1987-88, the per Capita GNP was the lowest in 1976-77. The GNP increased in the next two years but fell again during 1979-80. However, GNP and Per Capita GNP have recorded a consistent growth since 1980-81 onwards.

(b) The GNP and Per Capita GNP yearwise since 1975-76 upto 1987-88 and the projections for the next two years are presented in the statement enclosed. (*See* below)